

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या- 636 / 2014 / जयपुर
2. अपील संख्या- 637 / 2014 / जयपुर
3. अपील संख्या- 638 / 2014 / जयपुर
4. अपील संख्या- 639 / 2014 / जयपुर

मैसर्स एस.के.टेलीकॉम,  
108, प्रथम मंजिल, वर्धमान कॉम्प्लैक्स, जौहरी बाजार, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

**बनाम**

1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर।
2. सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, संभाग प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

**उपस्थित :**

श्री अलकेश शर्मा,

अभिभाषक।

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05.09.2017

**निर्णय**

1. उक्त चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 61 एवं 55 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	क.नि.वर्ष	क.नि.अधि. के आदेश	अपी. अधि. के आदेश	अन्तर कर	ब्याज
636 / 14	288 / अपील्स-II / आरवीएटी / जयपुर	10-11	26.12.2013	14.03.2014	3,02,268	1,17,885
637 / 14	289 / अपील्स-II / आरवीएटी / जयपुर	11-12	26.12.2013	14.03.2014	15,93,313	4,30,195
638 / 14	290 / अपील्स-II / आरवीएटी / जयपुर	12-13	26.12.2013	14.03.2014	18,33,405	2,75,010
639 / 14	291 / अपील्स-II / आरवीएटी / जयपुर	13-14	26.12.2013	14.03.2014	10,08,114	40,325

2. उक्त चारों अपीलों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन संभाग प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 01.10.2013 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में मोबाईल बैट्री एवं मोबाईल

लगातार.....2.

*05/09/17*

*11*



चार्जर की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मोबाईल बैट्री एवं मोबाईल चार्जर अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में उक्त तालिका अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें बिक्रीत उत्पाद मोबाईल बैट्री एवं मोबाईल चार्जर पर आरोपित धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया तथा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा बैटरी को मोबाईल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशिष्ट अनुसूची-IV के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबकि उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि संख्या 12 में "Cellular Telephones" अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात् बैटरी अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित "Cellular Telephones" का पार्टस होने से प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलोच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मोबाईल बैटरी एवं मोबाईल चार्जर मोबाईल यंत्र का आवश्यक पार्ट है, जिसके बिना मोबाईल यंत्र कार्य नहीं कर सकता है। विशिष्ट मोबाईल बैटरी केवल मात्र विशिष्ट मोबाईल यंत्र में प्रयोग होती है एवं इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयुक्त बनाम जसवन्त सिंह चरण सिंह (1967) 19 एसटीसी 469 में प्रतिपादित किया है कि किसी वस्तु को उसके लोकप्रिय नाम के आधार पर ही मान्यता दी जानी चाहिये ना कि उसके तकनीकी अथवा वैज्ञानिक आधार पर। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित

लगातार.....3.

*Amal Kumar*  
05/09/17

*Handwritten signature*



किया गया है जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। अतः उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:-

- (i) The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016
  - (ii) The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 297/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Agencies, Ajmer Date 16-08-2015
  - (iii) Supreme Court of India Assistant Commercial Tax Officer Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik agencies, Ajmer Date 28-03-2016.
  - (iv) Supreme Court of India Assistant Commercial Taxes Officer Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur Dated 21.01.2015
  - (v) In the Supreme Court of India Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd.
  - (vi) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 05.06.2017.
  - (vii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 853 से 855/2015/जयपुर मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोरमेटिक्स लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 27.06.2017.
  - (viii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 436 से 439/2016/अलवर मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा०लि०, अलवर बनाम अपीलीय प्राधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 29.06.2017.
  - (ix) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2017
  - (x) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 235 से 237/2015/जयपुर मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2017
6. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि मोबाईल के साथ विक्रय की गई मोबाईल बैटरी एवं मोबाईल चार्जर पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी? इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय

लगातार.....4.

*Amr. Kumar*  
05/09/17

*20*



एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता आलौच्य अवधि के अनुसार 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है :-

".....This court in ACTO V. M/s Swastik Agencies(supra), had an occasion to consider a case where battery which was fitted into a Motor Car and this court, after taking into consideration few of the judgments, held that same rate is to be applied on sale of batteries as that of a motor Car, though there was a finding that the batteries which are to be fitted in Motor Cars can be used for other diverse purposes then too, this court came to the conclusion that a nominal sale be that as it may of such batteries could not alter the nature of the transaction, whereas in the instant case there is a specific certificate of the Army Authority that the said battery can only be used as a part/integral part of RCRs, admittedly entire sale is to the ARMY only and for specific use alone.

.....  
In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

.....  
The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery cannot be said to be an accessory rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehicle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon is not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated. Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my view, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया

*[Signature]*  
05/09/17

*[Signature]*

लगातार.....5.



बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधिसम्मत है। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9. जहां तक व्यवहारी द्वारा बिक्रीत बैटरी चार्जर का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय तिथि 17.12.2014 का सुसंगत वर्णन निम्नानुसार है :-

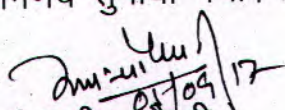
**"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."**

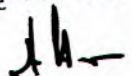
10. अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैटरी चार्जर पर कर दर संशोधित दर 5/5.5 प्रतिशत लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व बैटरी चार्जर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 के अनुसार सामान्य कर दर देय होगी।

#### आदेश

परिणामस्वरूप व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर की देयता है। अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैटरी चार्जर पर कर दर संशोधित दर 5/5.5 प्रतिशत लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व बैटरी चार्जर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. के अनुसार सामान्य कर दर देय होगी। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

11. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य

  
(वी. श्रीनिवास)  
अध्यक्ष